हाईवे पर जाम: रिलायंस कम्पनी की दादागिरी

फ़रीदाबाद (म.मो.) यहां से आगरा तक के हाईवे को चौड़ा करने के नाम पर अनिल अम्बानी की ठेकेदार कम्पनी रिलायंस इन्फ्रा ने पिछले करीब एक वर्ष से पूरा गदर मचा रखा है। शहर के बीचों-बीच से गुजरने वाले इस राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने का ठेका करीब 6 वर्ष पूर्व इस कम्पनी को दिया गया था। ठेका लेते ही कम्पनी ने टोल टैक्स वसूली का काम तो तुरन्त शुरू कर दिया परन्तु सड़क निर्माण का काम करीब एक वर्ष पूर्व शुरू किया है वह भी रोते-पीटते ढंग से।

अनिल अम्बानी ने ठेका तो जरूर ले लिया परन्तु काम करने का ठेका इसने आगे लार्सन एंड टुब्रो (एल एंड टी) कम्पनी को दे रखा है। अम्बानी तो केवल मुनाफ़ा डकारते हैं काम तो दूसरे लोग करते हैं। एल एंड टी वही कम्पनी है जिसने मैट्रो रेल का पूरा काम बड़ी ही सफ़ाई व कार्यकुशलता के साथ पूरा किया था। किसी भी शहरवासी को इस दौरान कतई कोई तकलीफ़ नहीं हुई। कारण स्पष्ट है। कोई भी काम करने वाली कम्पनी ठेके की शर्तों के अनुसार, काम शुरू करने से पूर्व यातायात को सुचारू बनाये रखने के प्रबन्ध ठेकेदार कम्पनी को करने होते हैं। जाहिर है इसके लिये अतिरिक्त खर्चा करना पड़ता है जो मैट्रो रेल ने तो किया परन्तु रिलायंस ने नहीं किया। वह करे भी क्यों जिसकी जेब में सरकार रहती हो। यह चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की। इसी नापाक गठजोड़ के चलते किसी अफ़सर की हिम्मत नहीं पड़ती जो रिलायंस कम्पनी की दादागिरी पर ज़रा भी अंकुश लगा सके।

यू तो रिलायंस की इस गुंडागर्दी के चलते सारा यातायात रोज़ाना ही प्रभावित रहता है परन्तु बीते सप्ताह तो इन्होंने कमाल ही कर दिया। सीकरी गांव के निकट एक साइड की पूरी सड़क अपने कब्ज़े में लेकर सारा यातायात दूसरी सड़क पर डाल दिया, वह भी सुबह-सवेरे के अति व्यस्त समय पर। इसके परिणाम-स्वरूप पलवल व बल्लबगढ की ओर 5-5 किलोमीटर लम्बे जाम लग गये। स्कूल-कॉलेज जाने वाले, दफ़्तरों व फैक्ट्रियों में जाने वाले कामग़ार घंटों जाम में फ़ंस कर रह गये और तो और एम्बुलेंसों के भी निकलने के लिये कोई जगह नहीं थी। ऐसे में एक छुटभैये भाजपाई नेता को रतन कॉन्वेंट स्कूल तक पहुंचाने के लिये स्थानीय पुलिस ने रेंगते हुए यातायात में घुसपैंठ करके, दूसरे वाहनों का रास्ता रोक कर इस नेता को निकाला ताकि वह स्कूल में पहूंच कर भाषणबाज़ी कर सके। यानी जनता जनार्दन के समय की कोई कीमत नहीं, समय केवल इन नेताओं का ही कीमती होता है।

देश में रोज़ग़ार की हकीकत

दुनिया भर में भारत सरकार ही ऐसी सरकार है जो बेरोज़ग़ारी के ठीक-ठीक आंकड़े ज़ारी नहीं करती। (भले ही वे आंकड़े वास्तविकता से कितनी ही दूर क्यों न हों) संयुक्त राष्ट्रसंघ से लेकर अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा जारी बेरोजगारी की तालिकाओं में भारत का स्थान अक्सर रिक्त रहता है।

स्वयं भारत सरकार जो भी आधे-अधूरे आंकड़े ज़ारी करती है वे बेरोज़ग़ारी दफ़्तर में पंजीकृत लोगों की संख्या होती है। यह संख्या एक लम्बे समय से चार करोड़ के आस-पास स्थिर है। इसके अलावा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की ओर से समय-समय पर आंकड़े ज़ारी किये जाते हैं जो बेरोजगारी दफ़्तर के आंकड़ों से ज़्यादा बेहतर तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। फ़िर भी ये आंकड़े यथार्थ को नहीं प्रस्तुत कर पाते।

बेरोजगारी के आंकड़ों की ये बातें एक घटना से ज़्यादा मोस-भज्जा ग्रहण कर लेती हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार के लिये करीब साढ़े तीन सौ चपरासियों की भर्ती की घोषणा हुई। इसके लिये न्यूनतम योग्यता कक्षा पांच पास होनी रखी गयी थी। इन थोड़े से पदों के लिए जब आवेदन आये तो पता चला कि उनकी संख्या 23 लाख थी। यानी एक पद के पीछे करीब सात हज़ार आवेदन।

आवेदकों की भारी-भरकम संख्या के साथ एक और चीज़ भी थी। पता चला कि इन आवेदकों में करीब डेढ लाख स्नातक थे जिसमें बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग और प्रबंधन की पढाई किये हुए लोग थे। पीएचडी किये लोग़ों की संख्या भी सैंकड़ों में थी।

चपरासी के पदों के लिये आवेदनों की यह हकीकत भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी के बारे में ज़ारी किसी भी आंकड़े से तारतम्य नहीं बैठ पाती। लेकिन मामला चपरासी के पदों का ही नहीं है। आज पूरे देश में यह सामान्य बात हो गयी है कि सरकारी नौकरियों में आवेदनों की संख्या पदों के मुकाबले सैंकड़ों-हज़ारों गुना होती है। केवल किसी विशेष योग्यता की मांग ही संख्या को सीमित रख पाती है।

आज पुलिस और सेना में भर्ती के समय यह नजारा होता है कि भर्ती के पास वाला शहर उन दिनों में खचाखच भर जाता है। रेलगाड़ियों में जगह मिलनी मुश्किल हो जाती है। अक्सर ये मौके हादसों समय बन जाते हैं।

रेलवे वगैरह में भर्ती के समय भी यही होता है। तब तकनीकी या बाबू की कुछ रिक्तियों के लिये सारे देश से प्रत्याशी पहुंच जाते हैं। कुछ साल पहले पश्चिम रेलवे द्वारा भर्ती के समय तो शिव सेना और मनसे ने इसे उत्तर भारतीयों के खिलाफ़ मुहिम का मौका बना लिया था।

चपरासी के पदों के लिये आवेदनों की यह हकीकत भारत सरकार द्वारा बेरोजगारी के बारे में ज़ारी किसी भी आंकड़े से तारतम्य नहीं बैठ पाती। लेकिन मामला चपरासी के पदों का ही नहीं है। आज पूरे देश में यह सामान्य बात हो गयी है कि सरकारी नौकरियों में आवेदनों की संख्या पदों के मुकाबले सैंकड़ों-हज़ारों गुना होती है। केवल किसी विशेष योग्यता की मांग ही संख्या को सीमित रख पाती है। आज पुलिस और सेना में भर्ती के समय यह नजारा होता है कि भर्ती के पास वाला शहर उन दिनों में खचाखच भर जाता है। रेलगाड़ियों में जगह मिलनी मुश्किल हो जाती है। अक्सर ये मौके हादसों समय बन जाते हैं।

ये सारी घटनाएं एक ओर इस तथ्य को बयां करती हैं कि देश में बेरोज़गारी की स्थिति भयानक है। इसमें बड़ी मात्रा में भांति-भांति के पढे-लिखे बेरोजगार हैं। सामान्य स्नातकों से लेकर तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों की एक लम्बी कतार है। तकनीकी शिक्षा के निजीकरण के इस जमाने में यह और भयानक इसलिये हो जाता है कि मध्यमवर्गीय नौजवान अक्सर कर्ज लेकर या पैत्रिक सम्पत्ति की कीमत पर यह शिक्षा हासिल करते हैं।

बेरोजगारी के इस आलम में दूसरी चीज़ सरकारी नौकरियों की महत्ता है। ये नौकरियां न केवल रोज़ग़ार की सुरक्षा प्रदान करती हैं बल्कि भ्रष्टाचार के जरिये और समृद्ध हो जाने का रास्ता भी हैं। निजी क्षेत्र के मुकाबले इन नौकरियों में तनख्वाहें और सुविधाएं भी काफ़ी बेहतर हैं।

इसीलिये गरीब और मध्यम वर्गीय आबादी में हर कोई इस तरह की नौकरी पाना चाहता है। इसके लिये जो मारा-मारी है इसके चलते इन नौकरियों की कीमत बहुत बढ गयी है यानी भर्ती करने वाले बाबू-अफ़सरों से लेकर मंत्री तक इसमें खूब उगाही कर रहे हैं। चपरासी-बाबू की नौकरी के लिये भी पांच, दस या बीस लाख रुपये आम हो गये हैं। मध्य प्रदेश का व्यापमं घोटाले तो बस इसका एक उदाहरण है। मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त गुजरात में पांच हज़ार रुपये की ठेके वाली नौकरियों की दर भी दस-बीस लाख रुपये हैं। लोग ये नौकरियां इतने महंगे दाम में इसलिये खरीद रहे हैं कि वे सोचते हैं कि भविष्य में ये नौकरियां स्थाई हो जायेंगी।

इन सबके बीच सरकारें हैं कि अपनी नौकरियों में लगातार कटौती करती जा रही हैं जो पद निहायत जरूरी हैं उन्हें ठेके पर भर रही हैं। देश में आज रोज़ग़ार की यही हकीक़त है। यह हकीकत इस दिशा में भी संकेत है कि ऐसा बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला।

-नागरिक

स्मार्ट सिटी: यानी जनता को लूटने का एक और बहाना

फ़रीदाबाद (म.मो.) स्वच्छता अभियान की नौटंकी करके जनता के सिर पर स्वच्छता टैक्स लगाने के बाद अब यह भाजपाई सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता की जेब काटने की तैयारी में है। पूरे डेढ साल के स्वछता ड्रामे के बावजूद गंदगी के ढेर ज्यों के त्यों व जहां के तहां सड़ रहे हैं। सड़ें भी क्यों न, नेताओं द्वारा भाषणबाज़ी व झाड़ू हाथ में लेकर फ़ोटो खिचाने से सफ़ाई हो ही नहीं सकती, सफ़ाई तो केवल सफ़ाई करने से ही हो सकती है।

देशव्यापी स्वच्छता अभियान के साथ-साथ अब स्मार्ट सिटी की नौटंकी पूरे ज़ोर पर है। कोई ठोस काम करने की अपेक्षा भाजपा सरकार जनता को घुम्मन-घेरी में डाले रखने के लिये यह सारी कवायद कर रही है। स्मार्ट सिटी के लिये फ़ार्म छपवा कर पोलिंग कराई जा रही है। इस फ़ार्म में वाहियात की बकवासबाज़ी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इसके अलावा ब्रांड एम्बसेडर की नियुक्ति, गोष्ठियां व तमाम तरह के तमाशों में जनता को उलझा कर रखा जा रहा है। कुल मिलाकर उसके पीछ नेताओं व सम्बन्धित अफ़सरों का एकमात्र उद्देश्य जनता का अधिक से अधिक पैसा डकारना है। केन्द्र सरकार की कथित ग्रांटों के अलावा शहर की जनता पर भी 'स्मार्टसिटी' नाम से नया टैक्स लगाने की भी योजना है।

विदित है कि इससे पूर्व जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूवल मिशन के नाम पर भी करीब 1500 करोड़ रुपये इस नगर का निगम डकार चुका है। उसके बावजूद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी मिशन के तहत शहर की सीवर व्यवस्था को सुचारू करने तथा सीवेज के ट्रीटमेंट प्लांट लगाने थे। इसी काम के लिये यमुना एक्शन प्लान के भी करीब 500 करोड़ डकार चुके निगम से आज तक सीवरेज व्यवस्था नहीं सुधरी है। जगह-जगह सीवरेज उफ़न कर गलियों में कीचड़ भर रहे हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों में न पहुंच कर सीधे गुड़गांव व आगरा कैनाल के अलावा यमुना नदी में छोड़ा जा रहा है। पीने के पानी का तमाशा तो हर वर्ष गर्मियों में सब को रूलाता ही है जबकि हजारों करोड़ रुपया रैनीवैल परियोजना के नाम पर डकारा जा चुका है। यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने एवं पब्लिक ट्रांस्पोर्ट व्यवस्था को मजबूत करने के लिये 200 नई बसें खरीद कर इस शहर को दी गयी थीं जो दो-ढाई बरस तक तो बेकार खड़ी रहीं। जैसे-तैसे चलने के बाद अब आधे से अधिक नकारा हो चुकी हैं, थोड़े दिनों बाद बाकी भी कंडम घोषित कर दी जायेंगी।

सरकार एवं इसकी नाकारा, हरामखोर एवं भ्रष्ट मशीनरी किसी भी काम के लायक नहीं बची है। हां जनता को बरगला कर, मूर्ख बनाकर लूट मार के नये-नये उपाय खेजने में पूरी माहिर है। शहर भर की सड़कों व गलियों में इस कदर सामान बिखरा रहता है कि आनाजाना मुश्किल हो जाता है। बाज़ारों में दुकान के भीतर इतना सामान नहीं होता जितना उसके बाहर रखा होता है। कोई भी बाज़ार ऐसा नहीं बचा जिसकी आधे से अधिक सड़क इस तरह के सामानों से न घेर ली गयी हो। इससे सम्बन्धित सचित्र समाचार आये दिन अखबारों में छापे जा रहे हैं। दिखावे के नाम पर, कभी-कभार, इन्हें हटाने का नाटक तो जरूर किया जाता है, परन्तु हटाया नहीं जाता।

अवैध कब्ज़ों की तर्ज़ पर अवैध निर्माण इस शहर की बड़ी समस्या है। सरकारी सांठ-गांठ के बल पर लोग अपने प्लाटों पर तो अवैध निर्माण करते ही हैं, साथ लगती सरकारी ज़मीन भी नहीं बख़्शते। घूसखोर अधिकारी सब कुछ देखते हुए भी अंधे बने रहते हैं। अवैध कॉलोनियों के निमार्ण में तो नेताओं की बराबर हिस्सेदारी रहती है। सड़कों पर अवारा घूमते कुत्ते व गायों के झुंड तो इस स्मार्ट सिटी की शोभा में चार चांद लगाये हुए हैं। साल भर में 25 से 30 हज़ार तक लोग इन कुत्तों के काटे के शिकार होते हैं। गायों व सांडों से भी कम दुर्घटनायें नहीं होती। साल में एक-दो तो घातक दुर्घटना भी हो जाती है। इसके अलावा रात में गौ-तस्करों से होने वाली मुठभेड तो अब एक आम बात हो गयी है। इस तरह की अनेकों छोटी-बड़ी समस्यायें नगरवासी झेल रहे हैं, जिनसे मुक्ति मिलने पर नगर स्वत: स्मार्ट हो जायेगा। **इसके लिये न तो किसी फ़ार्म छपवा कर पोलिंग कराने की जरूरत है न किसी ब्रांड एम्बसेडर की और न ही किसी अन्य तमाशे की। जरूरत है तो केवल सरकारी रिश्वतखोरी व हरामखोरी को समाप्त करके कायदे कानूनों को लागू करने की।**

एक सेठ की मनमानी

मैं एक फ़र्म में काम करता हूं जहां एक वाकया हुआ। जो इस प्रकार है कि हमारे सेठ एक सभा का चुनाव लड़ रहे हैं जो कि सेठ के लिये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चुनाव में सभी चुनाव लड़ने वाले काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। इसके मद्देनज़र हर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति चाहता है कि मेरी ही जीत हो। लेकिन कुछ लोग अपने काम को सफ़ल बनाने के लिये कुछ अन्य लोगों का भी इस्तेमाल करते हैं। जिनका इस चुनाव में कोई रोल नहीं है।

जैसा कि फ़र्म में काम करने वाले मज़दूरों के साथ हुआ कि सेठ का चुनाव लड़ने के लिये नामांकन होना था और उनके पास भीड़ जुटाने के लिए कोई और लोग नहीं थे। इसलिए सेठ ने सोचा कि दुकान के मज़दूरों को ही बुला लेते हैं तो नामांकन से एक दिन पहले सारे स्टाफ़ (मज़दूरों) से कह दिया गया कि आप सबको कल फ़लां-फ़लां जगह इतने समय पर पहुंचना है। लेकिन सेठ के कहने पर कोई भी मज़दूर वहां नहीं पहुंचा।

अगले दिन जब सब दुकान पर पहुंचते हैं तो सेठ सबसे पूछते हैं कि तुम सब कल क्यों नहीं पहुंचे। और कुछ अपशब्द भी कहे।

इससे नुकसान यह हुआ कि सेठ ने मुनीम से कहा कि इस महीने सेलरी एडवांस 10 तारीख के बाद देना। जब स्टाफ़ के लोग 4 तारीख को सेलरी एडवांस मांगने गये तो मुनिम ने कहा कि सेठ का आदेश है कि सेलरी एडवांस इस बार 10 तारीख के बाद मिलेगा तो अब लोग अपने घर का किराया, राशन, बच्चों की फ़ीस इत्यादि कहां से देंगे। क्या हम और हमारे परिवार को 6 दिन भूखा रहना पड़ेगा? चलो बड़े तो मान जायेंगे, पर बच्चों का क्या होगा? क्योंकि हम मज़दूरों को कोई उधार भी देने को राज़ी ही नहीं होता। क्योंकि हम मज़दूर हैं और हमारी कोई गारण्टी नहीं होता है। लोग स्वतंत्रता के दिन कहते हैं कि ''हम आजाद हैं'' लेकिन ये ''कैसी आज़ादी'' है। मै आज तक नहीं समझ सका?

-एक नागरिक